

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 1968 (आषाढ़ 29, 1890)

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 1968 (ASADHA 29, 1890)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जून 1968 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 24th June 1968 :—

क्र.सं.	संख्या और तारीख	द्वारा जारी किया गया	विषय
Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
118	No. 60-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	Ministry of Commerce	Revalidation of actual user licences.
	No. 61-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968	-do-	Errata No. (iii)—Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 62-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968	-do-	Errata No. (iv)—Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 63-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968	-do-	Terms and conditions governing the issuance of import licences, financial under International Development Association credits—78-IN, 92-IN & 97-IN.
	No. 64-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Import of radio components by S.S.I. Units --April, 1967—March, 1968 period.
	No. 65-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Errata No. 3—Import Policy for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 66-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 67-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969—Import of plant and machinery.
	No. 68-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Import Policy for Regd. Exporters for the year April 1968—March, 1969—Release Orders for import of canalised items.
	No. 69-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1968—March, 1969.
	No. 70-ITC(PN)/68, dated 18th June, 1968.	-do-	Export effort by priority and other industries—Production of evidence regarding.
119	No. WB-15(24)/67, dated 20th June, 1968.	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation.	Accepting the recommendations of the Wage Board.
120	No. 117-ITC(PN)/68, dated 20th June, 1968.	Ministry of Commerce.	Import of printing machinery falling under S.No. 67(1)(i)/V during April, 1968—March, 1969 period.
121	No. 118-ITC(PN)/68, dated 24th June, 1968.	-do-	Import policy for raw materials, components and spares, for units engaged in priority and other industries during April, 1968—March, 1969.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जान चाहिए।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूचि (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 539	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 3403
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	767	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	331
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं		भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	589
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	633	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	281
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम		भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	85
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट		भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	219
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1661	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	133

पूरक संख्या 29—

13 जुलाई 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1203
22 जून 1968 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1217

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page 539
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	767
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	633
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1661

PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	Page 3403
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	331
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	589
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	281
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	85
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	219
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	133
SUPPLEMENT No. 29—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th July 1968	1203
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 22nd June 1968	1217

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 1968

सं० 45-प्रेज/68—राष्ट्रपति प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारियों की सराहनीय सेवा के लिये “प्रादेशिक सेना अलंकृषण” प्रदान करते हैं :—

मेजर ईश्वर दयाल (टी० ए०-40162), इन्फैंट्री ।
मेजर जयन्ती रमैया (टी० ए०-40174), इन्फैंट्री ।
मेजर वीर सिंह (टी० ए०-40263), इन्फैंट्री ।
मेजर साही राम (टी० ए०-40283), इन्फैंट्री ।
(रिटायर्ड) ।

मेजर थोडुंगन तैथ्यू जोंगफ (टी० ए०-40296), इन्फैंट्री ।
(रिटायर्ड) ।

दिनांक 11 जुलाई, 1968

सं० 46-प्रेज/68—शनिवार, दिनांक 11 मई, 1968 के भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं०-30 प्रेज I 68, दिनांक 3 मई, 1968 में निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित किया है ।

क्रम संख्या 5-7 के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 के अंतिम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य पढ़ा जाए:-

“सूबेदार मेजर चन्द्रभान, मेसन दास राम तथा पायेंनीयर सोम बहादुर गुहंग ने कुली को बचाने के लिये सखेच्छा से रोहतांग दर्रा जाने के लिये अपने आप को अर्पित किया ।”

व० जे० मोर, राष्ट्रपति के उप-सचिव

समाज कल्याण विभाग

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 जुलाई 1968

सं० एफ० 13-9/67-एम० डब्ल्यू०-2—दिनांक 27 अक्टूबर 1967 के इसी संख्या के इस विभाग के संकल्प, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग में बाल कल्याण कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी, का आंशिक संशोधन करते हुए तथा इस विभाग के इसी सं० के दिनांक 21 मार्च 1968 के संकल्प के अनुवर्तन में भारत सरकार समिति द्वारा रिपोर्ट पेश करने की तारीख को 31 अगस्त 1968 तक सहर्ष बढ़ाती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा योजना आयोग के पास भेज दी जाय ।

आदेश है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो ।

बी० एस० रामदास, उप-सचिव

योजना आयोग

संकल्प

लघु उद्योगों के लिये पैनल

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1968

सं० वी० एस० आई०/27(4)/68—योजना आयोग इस संकल्प के द्वारा प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लघु उद्योगों के लिए एक पैनल का गठन कर रहा है । यह पैनल तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) और बाद के दो वर्ष 1966-67 एवं 1967-68 में हुई प्रगति का अध्ययन करेगा और 1969 से 79 तक के दस वर्षों की पृष्ठभूमि में चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में इन उद्योगों के विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग को सलाह देगा । पैनल में ये होंगे :—

1. श्री आर० बैकटरामन, सदस्य (उद्योग) 'अध्यक्ष
योजना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एन० श्रीरामा रेड्डी, संसद सदस्य, सदस्य
13-बी, फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
3. डा० पी० एस० लोकनाथन, "
62, श्रीनगर कालोनी, मद्रास-15 ।
4. श्री ए० आर० भाट, अध्यक्ष, "
भारतीय लघु उद्योग संघ संगठन,
लघु उद्योग कुटी,
23-बी/2, रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 ।
5. श्री जी० एल० बंसल, महामन्त्री, "
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बरों
का संघ, फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली-1 ।
6. श्री ए० के० भिवानी, अध्यक्ष, "
लघु उद्योगों के लिए विशेष समिति,
ए० आई० एम० ओ०, जीवन सहकार,
श्री फीरोजशाह मेहता रोड, बम्बई-1 ।

7. श्री जी० पी० नेवलकर, अध्यक्ष, सदस्य
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लि०,
बोम्बे लाइफ बिल्डिंग, 5वीं मंजिल,
45, बीर नरीमन रोड, बम्बई-1
8. श्री एल० सी० जैन, महा सचिव, ,
भारतीय सहकारी संघ,
4 राउज एवेन्यू, नई दिल्ली
9. श्री आर० गणेशन, अध्यक्ष, ,
मद्रास राज्य लघु उद्योग संघ,
44, माउन्ट रोड, मद्रास-15
10. श्री एम० एस० पार्थसारथी, ,
द्वारा, मै: स्टैण्डर्ड पब्लिशिंग फ़ैक्ट्री
सुपर ए०-5 और 6, औद्योगिक बस्ती,
गुड्डुली, मद्रास-32
11. श्री एस० के० चौधरी, अध्यक्ष, ,
छोटे पैमाने के अलौह धातु उद्योग संघ,
42/1, स्टैण्ड रोड, कलकत्ता-7
12. श्री एस० एन० शिवपुरी, सहायक स्वचालित ,
उद्योग (प्रा०) लि०,
309, बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट,
कलकत्ता-12
13. श्री के० एन० आर० रामानुजन, प्रमुख अधि- ,
कारी, औद्योगिक वित्त विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया,
पो० बैग नं० 100, बम्बई-9
14. श्री जे० एस० वाण्येय, ,
प्रमुख अधिकारी (लघु उद्योग),
केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक आफ इंडिया,
पो० बाक्स नं० 12, बम्बई-1
15. श्री सी० आर० सुंदरम, ,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम,
ओखला औद्योगिक बस्ती के निकट,
नई दिल्ली-20
16. प्रधानाचार्य-निदेशक, ,
लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्था,
हैदराबाद
17. श्री के० बी० राव, ,
सलाहकार (उद्योग एवं खनिज)
योजना आयोग
18. श्री के० बालचन्द्रन, संयुक्त सचिव, ,
औद्योगिक विकास और समवाय कार्य
मन्त्रालय
19. श्री के० एल० ननजप्पा, ,
विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
20. डा० जी० के० मल्होत्रा, सदस्य-सचिव
संयुक्त सचिव, योजना आयोग

2. यह पैनल अध्ययनों के लिए समितियां बना सकता है और सदस्यों को सहयोजित कर सकता है।

3. पैनल या उसकी समितियों की जितनी बार आवश्यकता हो नई दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर बैठक हो सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये और सभी संबंधितों को भेजी जाए।

संकल्प

हथकरघा, विद्युत्करघा, खादी तथा ग्रामोद्योग, दस्तकारी, रेशम, उद्योग तथा नारियल जटा उद्योग के लिये पैनल

सं० बी० एस० आई०/27(5)/68—योजना आयोग इस संकल्प के द्वारा प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए हथकरघा, विद्युत् करघा, खादी तथा ग्रामोद्योग, दस्तकारी, रेशम उद्योग तथा नारियल उद्योग के लिए पैनल का गठन कर रहा है। यह पैनल तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) और उसके बाद के दो वर्ष अर्थात् 1966-67 तथा 1967-68 के दौरान हुई प्रगति का अध्ययन करेगा तथा भावी दस वर्ष 1969-79 की पृष्ठभूमि में चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में इन उद्योगों में विकास के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग को सलाह देगा। इस पैनल में ये होंगे :—

1. श्री आर० वेंकटरमण, सदस्य (उद्योग), अध्यक्ष
योजना आयोग
2. श्री चन्द्रशेखर, संसत्सदस्य, सदस्य
3, साथ एवेन्यू, नई दिल्ली-11
3. श्री ए० जी० कुलकर्णी, संसत्सदस्य, ,
86, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4. डा० टी० एन० सिंह, संसत्सदस्य, ,
(अध्यक्ष, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड)
16, अशोक रोड, नई दिल्ली
5. श्री महावीर दास, संसत्सदस्य, ,
(उपाध्यक्ष, केन्द्रीय रेशम बोर्ड)
217, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1
6. श्री इरा सेनियान, संसत्सदस्य, ,
(सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड),
56, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1
7. श्री यू० एन० डेबर (अध्यक्ष, खादी तथा ,
ग्रामोद्योग आयोग),
3, इरलारोड, विले पार्ले (वेस्ट) बम्बई-56
8. श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, ,
2, केनिंग रोड, नई दिल्ली
9. श्री ए० आर० भाट, (अध्यक्ष, भारतीय ,
लघु उद्योग संघ संगठन, लघु उद्योग कुटी,
23, बी०/2, रोहतक रोड, नई दिल्ली-5

10. श्री विचित्र नारायण शर्मा, (सदस्य, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड), 9, शाहजहां रोड, लखनऊ	सदस्य	आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए।
11. श्री टी० रमेश यू० पाई, (उपाध्यक्ष, नारियल जटा बोर्ड), मनिपाल (मंसूर राज्य)।	"	भैरव दत्त पाण्डे, सचिव, योजना आयोग
12. श्रीमती किट्टि शिवा राव, (उपाध्यक्ष अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ब्लॉक-7 (वैस्ट) रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22	"	विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1968
13. श्रीमती पुपुल जयकर, कार्यकारी निदेशक, हैन्डीक्राफ्ट एन्ड हैन्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, लोक कल्याण भवन, 11-ए, राजज एवेन्यू लेन, नई दिल्ली।	"	संकल्प सं० फा० 47(1)/67-प्रशा० 1 (वि० वि०) रा० भा०— विधि मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने वाले संकल्प सं० फा० 47 (1)/67 प्रशा० 1 (वि० वि०) तारीख 4 अगस्त 1967 का अतिरिक्त उपान्तरण करके, भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि श्री वेद व्यास और डा० एल० एम० सिधवी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय को भी उन सदस्यों के अतिरिक्त, जिनके नाम पहले अधिसूचित किए जा चुके हैं, सलाहकार समिति का सदस्य होना चाहिए।
14. श्री एम० सोमाप्पा, अध्यक्ष, आल इण्डिया हैन्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग कारपोरेशन सोसायटी लिमिटेड, जी० पी० ओ० ब्रोक्स-1 530, बम्बई-1	"	आदेश 2. आदेश दिया जाता है कि एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान-मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लोकसभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।
15. श्री प्रगादा कोटिह, महा सचिव, आन्ध्र प्रदेश हैन्डलूम बीवर, कांग्रेस पो० ओ० निडूबरोलू, जिला गुंटूर (आन्ध्र प्रदेश)	"	3. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प साधारण जानकारी के लिए-भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। एस० एस० ममक, उप-सचिव
16. श्री एम० पी० नाचिमुधू, अध्यक्ष, तमिल नाडु हैन्डलूम बीवर कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, पी० बी०-33, इरोड	"	
17. श्री एल० पी० गुप्ता, भारतीय टैक्सटाइल कोआपरेटिव सोसायटी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेट इस्टर्न होटल, कलकत्ता-1	"	
18. श्री आर० श्रीनिवासन, एम०एस० (एस०सी०-आर०आई०पी०सी०) औद्योगिक विकास तथा समन्वय कार्य मन्त्रालय	"	वाणिज्य मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1968
19. श्री बी० एन० बनर्जी, विशेष सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय	"	
20. डा० डी० के० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, योजना आयोग।	सदस्य-सचिव	सं० 19(15)प्लॉट (बी०)/67—रबड़ के चार हैक्टर के छोटे बागानों की अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में, भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित, भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की 20 जून, 1968 की अधिसूचना सं० 19 (15) प्लॉट (बी०)/67 में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने समिति के प्रतिवेदन देने की अवधि को 15 जुलाई, 1968 तक बढ़ाने का निश्चय किया है। बी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

2. पैनल अपने अध्ययनों के लिए समितियों का गठन कर सकता है तथा सदस्यों को सहयोजित कर सकता है।

3. पैनल अथवा हमकी समितियों की जितनी बार आवश्यकता हो नई दिल्ली अथवा किसी अन्य स्थान पर बैठक हो सकती है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1968

संक्षेप

सं० 101(22)/68-पी० पी० डी०—भारत सरकार के संकल्प संख्या 101(26)/65-पी० पी० डी०, दिनांक 1 फरवरी 1966 में पेट्रोलियम उत्पादों के लिये मूल्यांकन व्यवस्था दर्शायी गई है, जो 31 दिसम्बर 1968 तक लागू है तथा जिसे सरकार के निर्णयानुसार और अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

2. भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि भारत में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का कम्पनियों के संग्रहालय केन्द्रों पर, अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारण करने के लिये एक समिति स्थापित की जाये। यह अधिकतम विक्रय मूल्य (व्यवस्था) वर्तमान व्यवस्था की समाप्ति की तारीख से लागू होगा।

3. समिति निम्न विषयों पर जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :—

- (i) उक्त विषय पर सरकार के आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए, शोधनशालाओं द्वारा उत्पादित शोधित पेट्रोलियम उत्पादों (विट्यूमैन्स को शामिल करते हुए) के शोधनशाला पर मूल्यों का आयात साम्य के आधार पर (जैसा कि अब है) या उत्पादन-लागत के आधार पर या किसी अन्य समुचित पद्धति पर निर्धारण;
- (ii) उपर्युक्त (i) के हवाले से सारे भारत में या प्रादेशिक आधार पर मूल्यों को एकसार लागू करने की सम्भावना;
- (iii) समरूप पदार्थों के (जिनका आयात किया जाये) उतरने पर लागत का निर्धारण;
- (iv) सारी शोधनशालाओं (अन्तर्देशीय शोधनशालाओं को शामिल करते हुए) को मूल्यांकन पाइंट बनाने की सम्भावना और इस विषय में देशीय कच्चे तेल के मूल्यों के आधार को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपायों का सुझाव देना ताकि इस सिद्धान्त को अपनाने के परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय शोधनशालाएं बुरी तरह से प्रभावित न हों;
- (v) भारतीय तेल निगम के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, विपणन (मार्केटिंग) तथा वितरण प्रभार और विपणन-कार्य पर लाभ का निर्धारण और इनका उपर्युक्त (i) और (iii) में बताये गये पदार्थों के लिये आवंटन;
- (vi) लुब्रीकेटिंग आयल्स, ग्रीसिज एवं स्पेशलटीज के बारे में अधिकतम विक्रय मूल्यों का निर्धारण; और
- (vii) अखिल भारत पेट्रोलियम ट्रेडर्स के महासंघ के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए, मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल आयल पर व्यापारियों की कमीशन की दरों का निर्धारण।

4. समिति राज्य सरकारों और अन्य बांछनीय सम्बद्ध संस्थानों के विचारों को मालूम करेगी तथा उनको ध्यान में रखेगी।

5. समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

- (i) श्री शान्तिलाल एच० शाह, चेयरमैन
लोक सभा सदस्य,
जन्मभूमि भवन, घोषा स्ट्रीट,
फोर्ट, बम्बई-1।
- (ii) श्री बी० एन० अदरकर, सदस्य
डिप्टी गवर्नर,
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया,
सेण्ट्रल आफिस,
बम्बई-1।
- (iii) डा० बी० नटराजन, सदस्य
डिप्टी डायरेक्टर जनरल,
नेशनल कांसिल आफ एप्साईड,
एकानामिक रिसर्च,
परिसिखा भवन,
11-इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-1।
- (iv) श्री एम० कृष्णन, सदस्य
मुख्य लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग),
नई दिल्ली-1।

6. पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के श्री एन० आर० ला, भारत सरकार के उप-सचिव की पदेन हैसियत से इस समिति के पूरे समय के लिये सचिव के रूप में कार्य करेंगे। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय समिति के लिये अपेक्षित सचिवालय सम्बन्धी सारी सहायता की व्यवस्था करेगा।

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

8. समिति का चेयरमैन जब कभी भी आवश्यक समझेगा, समिति की बैठक बुलायेगा और समिति 31 दिसम्बर 1968 या यथा-सम्भव उसके बाद सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, प्रधान मंत्री का सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा सैन्य सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, वाणिज्य, निर्माण एवं विविध के महालेखाकार और केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिये भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

माधव बी० राजवाड़े, संयुक्त सचिव

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली दिनांक 6 जुलाई 1968

संकल्प

सं० आई० पी० एण्ड एफ० सी० 12(10)/68—इस मंत्रालय के संकल्प सं० आई० पी० एण्ड एफ० सी० 12(10)/68 दिनांक 29 मार्च 1968 के अधीन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ सहयोग के लिये स्थापित भारतीय राष्ट्रीय समिति की सर्वप्रथम बैठक 8 अप्रैल 1968 को हुई और उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय समिति की एक उप-समिति की स्थापना की जाये जिसकी राष्ट्रीय समिति से जल्दी-जल्दी बैठकें हुआ करें और जो उसके कार्यों को करने में उसकी सहायता करे।

2. इस सिफारिश के अनुसार संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ सहयोग के लिये राष्ट्रीय समिति की एक उप-समिति की निम्न प्रकार स्थापना करने का निर्णय किया गया है :—

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन से सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति की एक उप-समिति का गठन

1. **नाम एवं स्थिति**—(क) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति की एक उप-समिति होगी जिसे अब उप-समिति कहा जायेगा।

(ख) यह उप-समिति औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध होगी जो उसके लिये सचिवालय की व्यवस्था करेगी।

2. **कार्य**—यह उप-समिति संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ सहयोग करने के लिये समूची भारतीय राष्ट्रीय समिति की बैठकों के लिये पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करेगी और राष्ट्रीय समिति की उसके कार्य करने में अन्य प्रकार से सहायता करेगी।

3. सचिव, औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय इस उप-समिति के अध्यक्ष होंगे।

4. **सदस्यता**—राष्ट्रीय समिति की उप-समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :—

- (1) अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री,
नई दिल्ली।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)
- (2) अध्यक्ष,
फेडरेशन आफ एसोसियेशन्स आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया,
पूना।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)

- (3) अध्यक्ष,
अखिल भारत निर्माता संगठन,
बम्बई।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)

- (4) सचिव,
वित्त मंत्रालय,
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)

- (5) सचिव,
वैदेशिक कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)

- (6) श्री वी० वी० द्रविड,
अध्यक्ष,
आई०एन०टी०यू०सी०,
श्रम शिविर शेहलातगंज,
इंदौर।
(अथवा उनका नामित व्यक्ति)

- (7) राष्ट्रीय समिति का सदस्य-सचिव जो उप-समिति के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

5. बैठकें :

उप-समिति की बैठक सामान्यतः तीन मास में एक बार होगी।

आदेश

आदेश दिया गया कि यह संकल्प भारत सरकार के सभी मंत्रालयों सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों योजना आयोग केबिनेट सचिवालय, लोक-सभा सचिवालय, राज्य-सभा सचिवालय तथा संसदीय-कार्य विभाग को भेजा जाये।

यह भी आदेश दिया गया कि सर्व-साधारण की सूचना के लिये संकल्प को 'भारत का राजपत्र' में प्रकाशित किया जाये।

के० बालचन्द्रन, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1968

सं० 27(1)/67-समन्वय (1)—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय को अधिसूचना सं० 27(1)/66-समन्वय (1), दिनांक 10 अगस्त 1966 द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में गठित पशु-विज्ञान अनुसंधान की स्थाई समिति के सदस्य डा० एन० के० पणिककर, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, जो कि परिषद् को नियमावली के नियम 77 एवं 11 (बो०) को व्यवस्थाओं के अनुसार स्थाई समिति के सदस्य नहीं रहे थे, को परिषद् को उसी नियमावली के नियम 75 एवं नियम 77 व 10 के अन्तर्गत खाद्य व कृषि मंत्री द्वारा

उक्त समिति में उनकी सदस्यता के शेष काल के लिए अर्थात् 22 जनवरी 1968 से 30 जुलाई 1969 तक अथवा उस समय तक जब तक समिति में उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न किया जाय—इन्हें जो भी अवधि पहले समाप्त हो—पुनः मनोनीत किया गया है ।

पी० एस० हरिहरन, उप-सचिव

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1968

संकल्प

सं० 5/1/67-पी० आर०—भारत सरकार ने 20 दिसम्बर 1967 के अपने संकल्प संख्या 5/1/67 पी० आर० द्वारा बुनियादी भूमि सुधार उपायों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और सामुदायिक विकास अभिकरणों की भूमिका का विस्तृत अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया था ।

2. उस संकल्प में यह अपेक्षा की गई थी कि दल अपने गठन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा । तथापि, अनेक कारणों से अध्ययन के नियत तारीख तक पूरा होने की सम्भावना नहीं है । अतः यथोचित विचार के उपरान्त भारत सरकार ने निर्णय किया है कि अध्ययन दल की अवधि और छः महीने, अर्थात् 20 दिसम्बर 1968 तक के लिये बढ़ा दी जाये ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आई० डी० एन० साही, अतिरिक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1968

संकल्प

विषय : भूटान के गजेटियर का संकलन

सं० एफ० 2-31/68-जी० यू०—राष्ट्रपति, भूटान के गजेटियर के संकलन के लिये एक सलाहकार समिति का सहर्ष गठन करते हैं । समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :—

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. राज्य शिक्षा मंत्री (कार्यभारी) | अध्यक्ष |
| भारत सरकार, नई दिल्ली । | |
| (प्रो० शेर सिंह) | |
| 2. सचिव, ई० ए०-I, | सदस्य |
| विदेश मंत्रालय, | |
| भारत सरकार, नई दिल्ली । | |
| 3. सचिव, | सदस्य |
| शिक्षा मंत्रालय, | |
| भारत सरकार, नई दिल्ली । | |

4. जी० ओ० सी०,
पूर्वी कमाण्ड, कलकत्ता । सदस्य

5. राजनीतिक अधिकारी,
भूटान सरकार, गंगटोक । सदस्य

6. भूटान सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य

7. सम्पादक (गजेटियर्स) शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली । सदस्य-सचिव

यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष द्वारा एक या दो सदस्यों को सहयोगित किया जा सकता है ।

2. सलाहकार समिति, विशेषज्ञों को अध्यायों के नियतन और उनके द्वारा तैयार किये गये अध्यायों के मसौदों पर टिप्पणियों जैसे सभी तकनीकी मामलों के बारे में सम्पादक को सलाह देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

ए० एम० डी० रोजारिओ, संयुक्त सचिव

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय

नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय

(श्रम और नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1968

प्रस्ताव

विषय : व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् के प्रस्ताव में संशोधन ।

सं० 101/68-टी० सी०—भारत सरकार के राजपत्र भाग I अनुभाग 1 में, दिनांक 21 अगस्त 1956 को प्रकाशित भूतपूर्व श्रम मंत्रालय (पुनः स्थापन एवं रोजगार महानिदेशालय) के प्रस्ताव सं० टी० आर०/ई० पी०-24/56, दिनांक 21 अगस्त 1956 को संलग्न योजना में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन कर दिये जायें ।

(1) निम्नलिखित, पैरा 4 का उप-पैरा 13 के रूप में, जोड़ दिया जाए ।

“4(13) शिक्षित अधिनियम 1961 के अधीन अथवा ऐसे कार्य करना जो समनुदेशित किए गए हों ।”

(2) वर्तमान पैरा 5(क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति-स्थापित करें ।

“5(क) केन्द्रीय पुनर्वास एवं श्रम मंत्री/श्रम एवं नियोजन उप-मंत्री अध्यक्ष

(3) वर्तमान पैरा 5(ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(ख) भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के सचिव।”

(4) वर्तमान पैरा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(ग) नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशक और नीचे दिये गये मंत्रालय/विभागों का एक-एक सदस्य” :—

- | | | |
|------|---|--|
| (1) | जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय। | |
| (2) | संचार मंत्रालय | |
| (3) | पर्यटन एवं सिविल विमानन मंत्रालय। | |
| (4) | लोहा एवं इस्पात विभाग | } इस्पात, खान एवं धातु मंत्रालय। |
| (5) | खान एवं धातु विभाग | |
| (6) | लघु उद्योग संगठन | } औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य-कलाप मंत्रालय। |
| (7) | बड़े एवं वरम्याने दर्जों के उद्योगों का संगठन | |
| (8) | सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान। | |
| (9) | छायाछात्रा के नियंत्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग)। | } निर्माण, आवास एवं पूर्ति मंत्रालय |
| (10) | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग। | |
| (11) | प्रतिरक्षा मंत्रालय | |
| (12) | वित्त मंत्रालय | |
| (13) | शिक्षा मंत्रालय | |
| (14) | रेल मंत्रालय | |
| (15) | सिचाई और बिजली मंत्रालय। | |
| (16) | सहकारिता विभाग | } खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय। |
| | | |

(17) योजना आयोग

(18) परमाणु-ऊर्जा विभाग

(19) भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि।

(20) तकनीकी विकास के महानिदेशक

जहां तक हो सके प्रतिनिधि तकनीकी अधिकारी ही होने चाहिये।

(5) वर्तमान उप-पैरा 5(घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(घ) एक-एक प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य सरकार तथा देहली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी, केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से”

(6) वर्तमान उप-पैरा 5(ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(ङ) कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशक, बम्बई”

(7) वर्तमान उप-पैरा 5(ट) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(ट)—नियोजन निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय”

(8) वर्तमान उप-पैरा 5(इ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“5(इ) प्रशिक्षण निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मंत्रालय—सदस्य सचिव

(9) निम्नलिखित पैरा 5(ग) का उप-पैरा (ङ) के रूप में जोड़ दिया जाए।

“5(ङ) अखिल भारतीय महिला संगठन का एक प्रतिनिधि।”

ग० जगन्नाथ, अवसर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th July 1968

No. 45-Pres./68.—The President is pleased to confer the “TERRITORIAL ARMY DECORATION” for meritorious service on the undermentioned commissioned officers of the Territorial Army :—

Major ISHWAR DAYAL (TA-40162), Infantry.
Major JAYANTI RAMAYYA (TA-40174), Infantry.
Major VEER SINGH (TA-40263), Infantry.
Major SAHI RAM (TA-40283), Infantry.
(Retired)

Major THOTUNGAL MATHEW JOSEPH (TA-40296), Infantry. (Retired)

The 11th July 1968

No. 46-Pres./68.—The following amendment to the President's Secretariat Notification No. 30-Pres./68 dated the 3rd May, 1968, published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 11th May, 1968 is hereby notified for general information.

Under serial number 5-7, the following sentence be substituted for the existing last sentence of para 1 “Subedar Major Chander Bhan, Mason Dasu Ram and Pioneer Som

Bahadur Gurung volunteered to go to Rohtang Pass to rescue the Porter."

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

RESOLUTION

New Delhi-1, the 8th July, 1968

No. F.13-9/67-SW-2.—In partial modification of this Department Resolution of even number dated the 27th October, 1967, setting up a Committee for preparation of an adequate programme of Child Welfare in the Department of Social Welfare, and in continuation of this Department Resolution of even number, dated the 21st March, 1968, the Government of India are pleased to extend further the date of submission of the report by the Committee up to the 31st August, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all the Ministries/Departments of the Government of India and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

Panel on Small Scale Industries

New Delhi, the 11th July 1968

No. VSI/27(4)/68.—Planning Commission hereby constitutes the Panel on Small Scale Industries for a period of one year in the first instance. The Panel will take stock of the progress made during the Third Five Year Plan (1961-66) and the subsequent two years, 1966-67 and 1967-68, and advise the Planning Commission on the various aspects of the programme for the development of these industries in the Fourth Five Year Plan (1969-74) in the ten years perspective of 1969-79. The Panel will consist of the following :—

Chairman

1. Shri R. Venkataraman, Member (Industry), Planning Commission.

Members

2. Shri N. Sri Rama Reddy, M.P., 13-B, Feroze Shah Road, New Delhi.
3. Dr. P. S. Lokanathan, 62, Srinagar Colony, Madras-15.
4. Shri A. R. Bhat, President, Federation of Associations of Small Industries of India, Laghoodyog Kutee, 23-B/2, Rohtak Road, New Delhi-5.
5. Shri G. L. Bansal, Secretary-General, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, Federation House, New Delhi-1.
6. Shri A. K. Bhimani, Chairman, Special Committee for Small Scale Industries, AIMO, Jeevan Sahkar, Sir P. M. Road, Bombay-1.
7. Shri G. B. Newalkar, Chairman, Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Ltd., Bombay Life Building, 5th Floor, 45, Veer Nariman Road, Bombay-1.
8. Shri L. C. Jain, Secretary-General, Indian Cooperative Union, 4, Rouse Avenue, New Delhi.
9. Shri R. Ganesan, President, Madras State Small Scale Industries Association, 44, Mount Road, Madras-15.
10. Shri M. S. Parthasarathy, C/o M/s. Standard Pencil Factory, Super A-5&6, Industrial Estate, Guindy, Madras-32.

11. Shri S. K. Chaudhury, President, Small Scale Non-Ferrous Metal Industries Association, 42/1, Strand Road, Calcutta-7.
12. Shri S. N. Shivapuri, Ancillary Automatic Industries (P) Ltd., 309, Bepin Behari Ganguli Street, Calcutta-12.
13. Shri K. N. R. Ramanujan, Chief Officer, Industrial Finance Department, Central Office, Reserve Bank of India, Post Bag No. 5100, Bombay-9.
14. Shri J. S. Varshney, Chief Officer (Small Scale Industries), Central Office, State Bank of India, Post Box No. 12, Bombay-1.
15. Shri C. R. Sundaram, Chairman, NSIC, near Industrial Estate, Okhla, New Delhi-20.
16. The Principal-Director, Small Industry Extension Training Institute, Yousufguda, Hyderabad.
17. Shri K. B. Rao, Adviser (I&M), Planning Commission.
18. Shri K. Balachandran, Joint Secretary, Ministry of I.D. & C.A.
19. Shri K. L. Nanjappa, Development Commissioner (SSI).

Member-Secretary

20. Dr. D. K. Malhotra, Joint Secretary, Planning Commission.
2. The Panel may for its studies constitute committees and coopt members.
3. The Panel or its committees may meet as often as may be necessary at New Delhi or any other place.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

RESOLUTION

Panel on Handloom, Powerloom, Khadi & Village Industries, Handicrafts, Sericulture & Coir Industries

No. VSI/27(5)/68.—Planning Commission hereby constitutes the Panel on Handloom, Powerloom, Khadi & Village Industries, Handicrafts, Sericulture & Coir Industries for a period of one year in the first instance. The Panel will take stock of the progress made during the Third Five Year Plan (1961-66) and the subsequent two years, 1966-67 and 1967-68, and advise the Planning Commission on the various aspects of the programme for the development of these industries in the Fourth Five Year Plan (1969-74) in the ten years perspective of 1969-79. The Panel will consist of the following :—

Chairman

1. Shri R. Venkataraman, Member (Industry), Planning Commission.

Members

2. Shri Chandra Shokhar, M.P., 3, South Avenue, New Delhi-11.
3. Shri A. G. Kulkarni, M.P., 86, Shahjahan Road, New Delhi.
4. Dr. T. N. Singh, M.P., (Chairman, All-India Handicrafts Board), 16, Ashoka Road, New Delhi.
5. Shri Mahabir Das, M.P., (Vice-President, Central Silk Board), 217, North Avenue, New Delhi-1.
6. Shri Era Sezhiyan, M.P., (Member, Central Silk Board), 56, North Avenue, New Delhi-1.
7. Shri U. N. Dhebar (Chairman, Khadi & Village Industries Commission), 3, Irla Road, Vile Parle (West), Bombay-56.

8. Smt. Kamala Devi Chattopadhyaya, 2, Canning Lane, New Delhi-1.
9. Shri A. R. Bhat, (President, Federation of Associations of Small Industries of India), Laghoodyog Kutee, 23-B/2, Rohtak Road, New Delhi-5.
10. Shri Vichitra Narain Sharma, (Member, Khadi & Village Industries Board), 9, Shah Najaf Road, Lucknow.
11. Shri T. Ramesh U. Pai, (Vice-Chairman, Coir Board), Manipal (Mysore State).
12. Smt. Kitty Shiva Rao, (Vice-Chairman, All India Handicrafts Board), Block VII (West), R. K. Puram, New Delhi-22.
13. Smt. Pupul Jayakar, Executive Director, The Handicrafts & Handloom Exports Corporation of India Ltd., Lok Kalyan Bhawan, 11-A, Rouse Avenue Lane, New Delhi-1.
14. Shri M. Somappa, President, All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd., G.P.O. Box No. 1530, Bombay-1.
15. Shri Pragada Kotaiah, General Secretary, Andhra Pradesh Handloom Weavers' Congress, P.O. Nidadbrolu, Guntur District (A.P.).
16. Shri M. P. Nachimuthu, President, Tamil Nadu Handloom Weavers Cooperative Society Ltd., P.B. 33, Erode.
17. Shri L. P. Gupta, The Indian Textiles Co. Pvt. Ltd., Great Eastern Hotel, Calcutta-1.
18. Shri R. Srinivasan, M.S. (SC-RIPC), Ministry of ID&CA.
19. Shri B. N. Banerji, Special Secretary, Ministry of Commerce.

Member-Secretary

20. Dr. D. K. Malhotra, Joint Secretary, Planning Commission.
2. The Panel may for its studies constitute committees and coopt members.
3. The Panel or its committees may meet as often as may be necessary at New Delhi or any other place.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

B. D. PANDE, Secy., Planning Commission

MINISTRY OF LAW (Legislative Department)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th June 1968

No. F.47(1)/67-Adm.I.(LD)-OL.—In further modification of the Resolution No. F.47(1)/67-Adm.I.(LD), dated the 4th August, 1967 constituting an Advisory Committee on Hindi for the Ministry of Law, the Government of India have decided that Shri Veda Vyasa and Dr. L. M. Singhvi, Advocates, Supreme Court, should also be Members of the Advisory Committee in addition to the Members whose names have already been notified.

ORDER

1. ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments; Union Territories; all the Ministries and Departments of the Government of India; President's Secretariat; Cabinet Secretariat; Prime Minister's Secretariat; Planning Commission; Comptroller and Auditor General; Accountant General, Central Revenues, New Delhi; the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. MAMAK, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 20th July 1968

No. 6/17/68-CS(I).—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in February 1969 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

- (i) Central Secretariat Service—Assistants' Grade;
- (ii) Railway Board Secretariat Service—Grade IV (Assistants);
- (iii) Armed Forces Headquarters Civil Service—Assistants' Grade;
- (iv) Posts of Assistant in certain Departments/Offices of the Central Government not included within the purview of the Central Secretariat Service/Indian Foreign Service (B)/Railway Board Secretariat Service.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to compete for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service/post not specified by them.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to compete. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 30th April, 1969.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Sikkim, or
- (c) a subject of Nepal, or
- (d) a subject of Bhutan, or
- (e) Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or
- (f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

- (iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then without a break. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Schedule Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st January, 1969, i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1945 and not later than 1st January, 1949.

Provided that a candidate who was born earlier than 2nd January, 1945 but not earlier than 2nd August, 1944 shall also be eligible for admission to the examination as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1969 only.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable:—

- (i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
- (ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
- (iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;
- (iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;
- (v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;
- (vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

- (viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

- (ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

- (x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

- (xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

- (xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I, or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services/posts, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, or of being found to have in his possession or accessible to him unauthorised papers, books or notes etc. in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the

examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service/post, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service/post.

NOTE.—Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application (c.f. Col. 25 of the application form) but a candidate may be assigned to any Service/post for which the examination is held.

18. The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

20. Candidates will be required to pass a test in typewriting conducted by the Commission, at a minimum speed of 30 words per minute, within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for a period the increments had been withheld.

21. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, the Railway Board Secretariat Service, Armed Forces Headquarters Civil Service, the posts of Assistants in the Election Commission of India and the Department of Tourism, are briefly stated in Appendix III.

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India

(vide Rule 6)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

D-8585
1 MAY 1969

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Dublin, The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The Dacca University, The University of Sind, The Rajshahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination (*Vide* Rule 6)

1. Alankar of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Banaras.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
7. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the All India Council for Technical Education.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Shri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, Provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.

APPENDIX II

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 4 or both, either in Hindi or in English. Paper 2 and Paper 3 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi should indicate their intention to do so in col. 7 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the papers in English.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects at the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) *Essay*: An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) *General English*:

(i) *Precis writing and drafting*: Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language.

(3) *Arithmetic*:

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The questions will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

(4) *General Knowledge including Geography of India*:

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) *Central Secretariat Service*.

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows:—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent) = Rs. 1,100—50—1,300—60—1,800—100—1,800.

(2) Grade I (Under Secretary or equivalent) = Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers Grade = Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants Grade = Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) Railway Board Secretariat Service.

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as recruitment, training, promotion etc., are concerned, are regulated by the Railway Board's Secretariat Service Scheme, which is broadly similar to the Central Secretariat Service Scheme.

(b) The Railway Board Secretariat Service consists of the following grades:—

(i) Assistant Director/Under Secretary—Rs. 900—50—1,250.

(ii) Section Officer—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iii) Assistants—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(d) Officers recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iii) The Armed Forces Headquarters Civil Service.

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows:—

(1) Senior Civilian Staff Officer (Class I) = Rs. 1,100—50—1,400.

(2) Civilian Staff Officer (Class I) = Rs. 740—30—800—50—1,150.

(3) Superintendent (Class II—Gazetted) = Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

(4) Assistant (Class II—Non-gazetted) = Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Superintendent shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Superintendent.

(2) Persons recruited direct as Assistant will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

(2) Election Commission, India.

The posts of Assistants in the Election Commission carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 like the posts of Assistants in the Central Secretariat Service. These posts are, however, not included in the Central Secretariat Service Scheme and the persons appointed to these posts will have no claim to be appointed to posts included in the cadre of the Central Secretariat Service.

2. The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On completion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of

probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. The next two higher grades are—

(1) *Section Officers' Grade*—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(2) *Under Secretaries' Grade*—Rs. 900—50—1,250.

(3) *Department of Tourism.*

The posts of Assistants in the Department of Tourism carry a scale of pay of Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 as prescribed for Grade IV of the Central Sectt. Service. These posts are, however, not included in the C.S.S. Scheme and the persons appointed to these post will have no claim to be appointed to the posts included in the cadre of the C.S.S.

The persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government from time to time. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in the discharge of the probationer from service.

On completion of the probation, the Government may confirm the probationer in his appointment, or if his work or conduct, has, in the opinion of the Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as the Government may consider necessary.

Assistants will be eligible for promotion to higher grade of Assistant Director (Administration) in the pay scale of Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTICE

New Delhi, the 6th July 1968

Appointment of Valuers under Section 4(3) of the Estate Duty Act, 1953

No. 5/77/68-ED.—In supersession of this Ministry's Notices No. 5/76/59-ED, dated the 27th August, 1962. No. 5/50/63-ED, dated the 27th December, 1963 and No. 5/20/63-ED, dated the 13th May, 1964, it is hereby notified for general information that the Central Government proposes to appoint qualified persons as Valuers under Sub-section (3) of Section 4 of the Estate Duty Act, 1953, and to fix a scale of charges for their remuneration.

2. The different kinds of properties of which valuation may be required to be made and the corresponding categories of Valuers are broadly as follows:

Sl. No.	Nature of Property	Category of Valuers
(1)	(2)	(3)
(1)	Immovable property other than agricultural lands and Coffee estates.	Engineer, Surveyor or Architect; Mining Engineer for mines and Quarries.
(2)	Agricultural lands	Specialist in Agriculture and Farm Valuation.

(1)	(2)	(3)
(3) Coffee Estates	..	Specialist in Coffee plantation.
(4) Stocks, Shares and debentures of a company not quoted in a recognised stock exchange including shares and debentures of a controlled company.	..	
(5) Share of a Partner in a partnership,	..	Accountant
(6) Business Assets including goodwill.	..	
(7) Jewellery, Precious Stones and Ornaments.	..	Specialist in Jewellery Precious Stones and Ornaments.
(8) Works of Art.	..	Specialist in Works of Art.
(9) Life Interest, reversions and interests in expectancy.	..	Actuary.
(10) Tea Estates.	..	Valuers for Tea Estates.
(11) Standing forests	..	Valuers for Standing forests.

3. In order that a person may be eligible for appointment as a Valuer in a particular category, he must satisfy the qualifications prescribed hereunder for that category:—

(I) *In the case of Engineer, Surveyor or Architect:*

- The valuer must either be a graduate in Engineering, Mining or Architecture of a recognised University, or be a member or hold a diploma of a recognised Institute or Institution of Engineers, Architects, Surveyors or School of Mines, the membership or diploma of which is recognised as sufficient qualification for the purposes of recruitment to superior posts and services under the Central Government; and
- he must have been in practice as consulting engineer, mining engineer, surveyor or architect for not less than seven years.

N.B. In the case of a person who is or was in the service of,

- a State or the Central Government, a period of seven years' continuous service as a gazetted officer may for this purpose be treated as equivalent to seven years' practice;
- a statutory Improvement Trust, Municipality, Municipal Corporation or a District Board, seven years service as a member of the Executive staff engaged on valuation work may be regarded as satisfying both conditions Nos. (i) & (ii) above.

(II) *In the case of a Specialist in Agriculture and Farm Valuation:*

- The valuer must be a graduate in Agricultural Economics or Agricultural Science with at least seven years experience as a Farm Valuer;

or

- He should have been in the service of a State Government for a total period of not less than seven years as—
 - An Agricultural Inspector; or
 - a Tahsildar; or
 - a Land Valuation Officer; or
 - a Settlement Officer.

(III) *In the case of a Specialist in Coffee Plantation:*

- The valuer must be the owner or manager of a Coffee Plantation of the size of at least 100 acres; and
- he must have at least seven years' experience in the plantation line,

(IV) *In the case of an Accountant :*

- (i) The Valuer must be a member of the Institute of Chartered Accountants of India; and
- (ii) he must have been in continuous practice as a Chartered Accountant for a period of not less than seven years.

N.B. In the case of a person who is or was in the service of a State or the Central Govt., a Municipality, Municipal Corporation or District Board, seven years continuous service connected with the audit and accounts or taxation work may be regarded as satisfying condition No. (ii) above.

(V) *In the case of a Specialist in Jewellery, Precious Stones and Ornaments :*

- (i) The Valuer must have been engaged in the business of Jewellery, Precious Stones or Ornaments for a period of not less than seven years; and
- (ii) his business or the business in which he is a partner must have had an annual turnover of not less than rupees one lakh in jewellery, precious stones or ornaments in each of the last three accounting years.

(VI) *In the case of a Specialist in Works of Art :*

The Valuer must be—

- (i) a member or an ex-member of the Art Purchase Committee,
- (ii) Principal or ex-Principal of a Government School of Art;
- (iii) Artist member or ex-Artist Member of the General Council or Fellow of the National Academy of Art (Lalit Kala Akademi),
- (iv) Director or ex-Director, Assistant Director or ex-Assistant Director of National Museum, New Delhi,
- (v) Officer-in-charge or ex-Officer-in-charge, Director or ex-Director, Assistant Director or ex-Assistant Director, Salarjung Museum, Hyderabad,
- (vi) Director or ex-Director, Prince of Wales Museum, Bombay,
- (vii) Superintendent or ex-Superintendent, Madras Museum,
- (viii) Director or ex-Director, Indian Museum Calcutta,
- (ix) Curator or ex-Curator of the National Gallery of Modern Art, New Delhi.
- (x) Director General or ex-Director General of Archaeology, Superintendent or ex-Superintendent of Archaeology.

(VII) *In the case of an Actuary :*

- (i) The Valuer must be a graduate of a recognised University;
- (ii) he must be a member of an Institute of Actuaries which entitles him to act as an Actuary under the Insurance Act, 1938, and
- (iii) he must have been in practice as an Actuary for not less than seven years.

N.B. In the case of an Actuary who is or was in the service of—

- (a) a State or the Central Government or an Insurance Company having an annual premium income of Rs. 20 lakhs, condition No. (iii) above may be deemed to be satisfied if the period of service and the period of practice as an Actuary together amount to not less than seven years;
- (b) the Life Insurance Corporation of India, all the three conditions Nos. (i) to (iii) above may be deemed to be satisfied if the period of service (including service with the merged Units of the Corporation) and the period of practice as an Actuary together amount to not less than seven years.

(VIII) *In the case of a Valuer for Tea Estates :*

- (a) he should be the owner or Manager of a tea plantation of the size of at least 100 acres which has a factory for manufacturing tea; and
- (b) he must have at least seven years' experience in the plantation line.

(IX) *In the case of a Valuer for Standing Forests :*(a) *Essential :*

- (1) He must be a Diploma holder in Forestry from a recognised institution,
- (2) He should have been in the service of a State or the Central Government as a Gazetted Forest Officer for a period of not less than seven years.

(b) *Desirable :*

He should have experience of preparation of working plans.

4. Any person who fulfils the qualifications set out above for any one of the categories of Valuers and who wants to have his name considered for appointment as a Valuer may apply to the Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), New Delhi.

5. The application of any person in the service of a State or the Central Government or a Statutory Corporation or Local Authority should be supported by a certificate from the employer to the effect that he has no objection to the applicant's appointment as a Valuer and to his undertaking any valuation work by virtue of such appointment.

6. On receipt of an application, the Central Government may require any other information to be furnished or may cause such enquiries to be made as it deems fit.

7. (1) The appointment of Valuers shall be for an initial period of five years and every person who has been so appointed may apply again for the renewal of his appointment for a similar period if he satisfies the qualifications prescribed for the time being.

(2) Further names of Valuers may be added in list to be published half-yearly.

(3) The Central Government may remove the name of any person from the list of Valuers if it finds him guilty of any misrepresentation in furnishing particulars of his qualifications and experience, or of any misconduct in connection with any valuation proceedings.

8. The scale of charges fixed for the remuneration of valuers is as under :

SCALE OF CHARGES

On the first Rs. 50,000/- of the property so valued, 1/2% of the value.

On the next Rs. 1,00,000/- of the property so valued, 1/4% of the value.

On the balance of property so valued .. 1/8 of the value.

WASIQ ALIKHAN

Deputy Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 10th July 1968

No. 19(15)Plant(B)/67.—In modification of Notification No. 19(15)Plant(B)/67 dated the 20th June, 1968 of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in Part I, Section I of the Gazette of India, regarding appointment of a Committee to go in depth into the economics of the small holdings of rubber up to 4 hectares, Government of India have decided to extend the period for submission of the Committee's report up to the 15th July, 1968.

B. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND
COMPANY AFFAIRS**

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th July 1968

No. IP&FC-12(10)/68.—The Indian National Committee for Cooperation with UNIDO set up under this Ministry's Resolution No. IP&FC-12(10)/68 dated the 29th March, 1968 met for the first time on the 8th April, 1968 and recommended *inter alia* that a small sub-Committee of the National Committee might be set up which may meet more often than the National Committee and assist it in the discharge of its functions.

2. In pursuance of this recommendation, it has been decided to set up a Sub-Committee of the Indian National Committee for Cooperation with UNIDO as follows :—

**CONSTITUTION OF A SUB-COMMITTEE OF THE
INDIAN NATIONAL COMMITTEE FOR COOPERATION
WITH UNIDO**

(1) *Name and Status*—(a) There shall be a Sub-Committee of the Indian National Committee for Cooperation with UNIDO hereinafter called the Sub-Committee.

(b) The Sub-Committee shall be attached to the Ministry of Industrial Development and Company Affairs which shall provide its Secretariat.

(2) *Functions* :—It will prepare the background material for the meetings of the full Indian National Committee for Cooperation with UNIDO and in other ways assist the National Committee in the discharge of its functions.

3. The Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industrial Development and Company Affairs shall be the Chairman of the Sub-Committee.

4. *Membership*—Membership of the Sub-Committee of the National Committee shall consist of

- (i) President,
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry,
New Delhi.
(or his nominee)
- (ii) President,
Federation of Associations of Small Industries of India,
Poona.
(or his nominee)
- (iii) President,
All India Manufacturers' Organisation,
Bombay.
(or his nominee)
- (iv) Secretary,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs),
New Delhi.
(or his nominee)
- (v) Secretary,
Ministry of External Affairs,
New Delhi.
(or his nominee)
- (vi) Shri V. V. Dravid,
President,
INTUC,
Shram Shivir Shehlataganj,
Indore.
(or his nominee)
- (vii) Member-Secretary of the National Committee who will also function as Member-Secretary of the Sub-Committee.

5. *Meetings*—The Sub-Committee shall ordinarily meet once in three months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India, all the State Governments, Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and the Department of Parliamentary Affairs.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. BALACHANDRAN, Jt. Secy.

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 2nd July 1968

ORDER

No. 51/1/65-CLH.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri J. K. Lal, Deputy Director of Inspection, New Delhi, an officer of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development & Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purposes of said section 209.

M. K. BANERJEE, Under Secy.
to the Company Law Board

**MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING
AND URBAN DEVELOPMENT**

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th July 1968

No. 5-1/67-MCH.—In continuation of the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development Resolution No. 5-1/67-MCH, dated the 6th January, 1968, regarding reconstitution of the Advisory Committee of the Countess of Dufferin's Fund, it has been decided that Smt. Rajni Devi, M.P. (Lok Sabha), shall also be a member of the Committee.

K. N. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY
DEVELOPMENT AND COOPERATION**

(Department of Agriculture—I.C.A.R.)

New Delhi, the 10th July 1968

No. 27(1)/67-CDN(I).—Under the provisions of Rule 75 read with Rules 77 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Dr. N. K. Panikkar, Director, National Institute of Oceanography, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, who ceased to be a member of the Standing Committee for Animal Sciences Research of the Council as constituted under this Ministry's Notification No. 27(1)/66-CDN(I), dated the 10th August, 1966, with effect from the 22nd January, 1968, under Rule 77 read with Rule 11(b) of these Rules has been renominated by the Minister of Food and Agriculture as a member of that Standing Committee for the unexpired portion of his term of Membership of the Committee, viz. from the 22nd January, 1968 to the 30th July, 1969, or till such time as his successor is nominated on that Committee, whichever period expires earlier.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

(Department of Community Development)

New Delhi, the 20th June 1968

RESOLUTION

No. 5/1/67-PR.—The Government of India in their Resolution No. 5/1/67-PR, dated December 20, 1967, had set up a Study Team to undertake a detailed study of the role of Panchayati Raj institutions and the Community Development agencies in the basic land reform measures.

2. In that Resolution, the Team was required to submit its report within a period of six months from the date of its constitution. For various reasons, however, the study is not expected to be completed by the due date. The Government of India after due consideration, have, therefore, decided that the term of the Study Team may be extended by another six months i.e. up to December 20, 1968.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

I. D. N. SAHI, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

Gazetteers Unit

RESOLUTION

New Delhi-1, the 5th July 1968

SUBJECT :—*Compilation of the Gazetteer of Bhutan.*

No. F.2-31/68-G.U.—The President is pleased to constitute an Advisory Committee for the Compilation of the Gazetteer of Bhutan. The composition of the Committee shall be as follows :—

Chairman

1. Minister of State (in charge), Ministry of Education, Government of India, New Delhi, (Prof. Sher Singh).

Members

2. Secretary, E.A.-I, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Education, Government of India, New Delhi.
4. G.O.C., Eastern Command, Calcutta.
5. Political Officer, Government of Bhutan, Gangtok.
6. A Representative of the Government of Bhutan.

Member-Secretary

7. Editor (Gazetteers), Ministry of Education, New Delhi.

The Chairman may co-opt one or two members, if necessary.

2. The Advisory Committee will advise the Editor on all technical matters such as the allocation of Chapters to the experts and comments on the draft of the Chapters prepared by them.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments and Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. M. D'ROZARIO, Jr. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT & REHABILITATION

(Directorate General of Employment and Training)

RESOLUTION

New Delhi, the 6th July 1968

SUBJECT :—*National Council for Training in Vocational Trades Amendment to the Resolution.*

No. 101/68-JC—The following further amendments in the scheme attached to the late Ministry of Labour (Directorate-General of Resettlement and Employment) Resolution No. TR/EP-24/56, dated the 21st August, 1956, published in the Gazette of India, Part I, Section I, dated the 21st August, 1956, shall be made :—

1. The following may be added as sub-para 13 of para 4 :—
“4(13) To perform such functions as are assigned by or under the Apprentices Act, 1961”.

2. Substitute the following for the existing para 5(a)

“5(a) The Union Minister of Labour and Rehabilitation/ Deputy Minister of Labour and Employment—Chairman.”

3. Substitute the following for the existing para 5(b)
5(b) “The Secretary to the Government of India, Department of Labour and Employment”.

4. Substitute the following for the existing para 5(c)

“5(c) The Director-General of Employment and Training and one representative each of :—

- | | |
|---|---|
| (i) Ministry of Transport and Shipping. | |
| (ii) Ministry of Communications | |
| (iii) Ministry of Tourism and Civil Aviation. | |
| (iv) Department of Iron and Steel | } In the Ministry of Steel, Mines and Metals. |
| (v) Department of Mines & Metals. | |
| (vi) Small Scale Industries Organisations. | } In the Ministry of Industrial Development and Company Affairs |
| (vii) Large and Medium Scale Industries Organisations. | |
| (viii) Public Sector Projects. | } In the Ministry of Works, Housing and Supply. |
| (ix) Controller of Printing (Department of Printing and Stationery) | |
| (x) Central public Works Department. | |
| (xi) Ministry of Defence. | |
| (xii) Ministry of Finance. | |
| (xiii) Ministry of Education. | |
| (xiv) Ministry of Railways. | |
| (xv) Ministry of Irrigation and Power. | |
| (xvi) Department of Co-operation | } In the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation. |
| | |
| (xvii) Planning Commission. | |
| (xviii) Department of Atomic Energy | |
| (xix) Textile Commissioner to the Govt. of India or his representative. | } In the Ministry of Commerce. |
| (xx) Directorate-General of Technical Development. | |
| | } In the Ministry of Industrial Development and Company Affairs |
| | |

The representatives will, as far as possible, be technical officers.

5. Substitute the following for the existing sub-para 5(d)
“5(d) One representative from each State Government and Union Territory of Delhi, Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Chandigarh, Goa, Daman and Diu and Pondicherry”.
6. Substitute the following for the existing sub-para 5(c)
“5(e) Director-General, Factory Advice Service and Labour Institute, Bombay”.
7. Substitute the following for the existing sub-para 5(k)
“5(k) The Director of Employment Exchanges, (Directorate-General of Employment and Training), Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation”.
8. Substitute the following for the existing sub-para 5(l)
“5(l) The Director of Training, (Directorate-General of Employment and Training, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation—Member Secretary.
9. The following may be added as sub-para (m) of para 5(c)
“5(m) One representative of an all India Women Organisation”.

G. JAGANNATHAN, Under Secy.

